16.33 hrs.

MOTION RE: NATIONAL POLICY FOR CHILDREN

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

> "कि यह सभा दिनांक 22 अगस्त, 1974 के राष्ट्रीय बाल नीति सम्बन्धी सरकारी संकल्प संख्या 1-14/74-सी डी डी पर, जो 26 अगस्त, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे यह प्रस्ताव रखने का मौका दिया । प्रस्ताव रखने के साथ साथ मैं उस महान विभूति को याद किए बिना नहीं रह सकता, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू जिनका आज महा-परिनिर्वाण दिवस है, उन्होंने अपने मरने के पहले राष्ट्र के नाम एक सम्बोधन में कहा था कि मेरे मरने के बाद कुछ लोग अगर मेरे बारे में सोचें तो मैं चाहूंगा कि वे कहे कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे दिल और दिमाग से हिन्दुस्तान को और हिन्दुस्तानवासियों को प्यार करता था और हर हिन्दुस्तानी उसकी हर खामी को भूल कर उसे बेहद प्यार करता था ।

16.34 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

आज वह प्रकाश नहीं रहा । शायद बच्चो का चाचा इसी दिन के लिए यह बात कह गया था कि देश का बच्चा जब उन्हें याद करेगा तो तो वह कहेगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे दिल दिमाग से देश के प्यारे बच्चों को बहुत प्यार करता था । आज उस दिवंगत आत्मा को हम प्रणाम करते हैं और इस दिवस पर बच्चों के हित के लिए एक प्रस्ताव जो आज सदन में प्रस्तुत हुआ है वह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी ।

देश में बच्चों की संख्या कितनी है यह सभी जानते हैं । आज हमारे सामने जब बच्चे आते हैं, उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा हमारे सामने आता है तो हम प्रफुल्लित होते हैं । लेकिन जब उन बच्चो की आखों में आंसू होते हैं तो मेरा और सारे सदन का मन बहुत दुखी होता है । 15 अगस्त, 1947 को उसी महान विभूति ने कहा था कि हमें उन आखो के आसू पोंछने हैं । आज सदन उस वायदे को पूरा करेगा, उस वायदे को पूरा करने में अपनी सारी शक्ति लगायेगा । इसी वास्ते आज हमने इसको यहा पर चर्चा का विषय बनाया है । पंडित जी बच्चों के बारे में और बच्चो से सम्बन्धित इस देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते थे उसका मैं एक छोटा सा उद्धरण प्रस्तुत करूंगा । उन्होंने कहा था

> But somehow the fact that ultimately everything depends on the human factor gets rather lost in our thinking of plans and schemes of national development in terms of factories and machinery and general schemes It is all very important we must have them; but ultimately of course it is the human being that counts and if the human being counts, well, he counts much more as a child than as a grown-up.

ये भाव उस राष्ट्र-निर्माता के थे जिसका आज महापरिनिर्वाण दिवस है ।

संविधान की धारा 15(3) में बहुत अच्छी बातें अंकित हैं । उसमें अंकित है कि बच्चों के विकास के लिए हम विशेष सुविधायें प्रदान कर सकते हैं, अन्य चीजों को छोड़ कर भी नया प्रस्ताव ला सकते हैं । संविधान की धारा (24) में लिखा हुआ है कि हम 14 साल के बच्चों से कोई कडा काम नहीं लेंगे, मेहनत का कोई ऐसा काम जिससे उसके शरीर

[श्री डी० पी० यादव]

और मन पर उसका पहुंचे इसी प्रकार से धारा 45 में हमने वायदा किया था कि 14 साल के हर बच्चे को हम अनिवार्य रूप से 8वीं कक्षा तक शिक्षा देंगे। किसी कारणवश हम वैसा नहीं कर पाये क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां और उलझनें हमारे सामने थीं लेकिन उसका आदर करते हुए हमारी कोशिश जारी है और जारी रहेगी। जब तक इस देश के बच्चे मजबूत नहीं होंगे तब तक यह देश बलवान नहीं हो सकता है। आज जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें सबसे अधिक आवश्यकता है अपने विचार को बदलने की। हमको अपना विचार बदलना होगा, खासकर बच्चों के प्रति अपने विचार को बदलना होगा। बच्चा सभी का है, बच्चा राष्ट्र का है, वह राष्ट्र का धन है, राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसी सन्दर्भ में बच्चों के प्रति क्या आस्था है और क्या उनकी शक्ति है, मैं अपने माननीय प्रधान मन्त्री के शब्दों को दोहराना चाहूंगा जो उन्होंने बच्चों के बारे में कहा है :

Our century is called the century of nuclear power and air and space travel. This is true of course but I would prefer to call it the Century of Child .

इससे अन्दाज लग रहा है कि इस देश के महान नेता के मन में बच्चों के प्रति क्या आदर है, बच्चों के प्रति क्या सम्मान है। 14 नवम्बर, को जो हम बाल दिवस मनाते हैं उस दिन दिल्ली में और अन्य शहरों में जब बच्चों की असेम्बली होती है तो हम किस प्रकार से उनको गले लगाते हैं जो इस बात का सबूत है कि हम बच्चों को अधिक प्यार करते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बहुत से कानून बने हैं। यूनाइटेड नेशन्स ने अपने ह्यूमन राइट्स के पालिसी रेज़ोल्यूशन में बच्चों के प्रति बहुत सारी बातें कही हैं और सद्भावना व्यक्त की है।

उनके अधिकार को दोहराया है। यूनाइटेड नेशन्स ने जो कुछ भी दोहराया हो, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि सारा यूनाइटेड इण्डिया इस बात के लिए कटिबद्ध हो, दृढ़प्रतिज्ञ हो कि हम बच्चों का कल्याण करेंगे केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि उसको आदमी बना कर। अतः यूनाइटेड नेशन्स से लेकर यूनेस्को और यूनिसेफ की श्रृंखलाएं जो हमारे पास हैं, आज हम उनको धरती पर लाएंगे और खास तौर से हिन्दुस्तान की धरती पर लाएंगे। इसी अभिप्राय से हम यह प्रस्ताव इस माननीय सदन के सामने लाए हैं।

इसमें मेरी ओर से अधिक अभिभाषण ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि छोटी सी पुस्तिका जो है, जिसमें चाइल्ड पालिसी रेज्योल्यूशन है, उसको माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। उसके अलावा भी आपके जो सुझाव और प्रक्रिया हम को मिलेगी, उस पर हम विचार करेंगे।

मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सरकारी मदद से ज्यादा गैर-सरकारी एफर्टस में विश्वास करता हूं और हमने ऐसा देखा है कि उससे ज्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं अपनी बाबत अधिक नहीं कहना चाहूंगा लेकिन एक छोटा सा कार्य मैंने अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए किया है और उसको करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मन मजबूत हो, इरादा पक्का हो, तो बच्चों की सेवा के लिए हर जगह सरकार की मदद की आवश्यकता हो, ऐसी बात नहीं है। श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी अभी मुझ से बात कर रहे थे कि बच्चों

के लिए कुछ करना है । एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं । जैसा कि मैंने ऊपर बतलाया है कि एक छोटा सा काम मैंने अपने क्षेत्र में पार्लियामेंटरी क्षेत्र में नहीं, बच्चों के लिए डिपथीरिया, व्हूपिंग कफ, टैटानस और पोलियो के बारे में किया । शुरू शुरू में जब यह एक्सपेरीमेंट किया, तो कुछ डाक्टरों को बुलाया और कुछ डाक्टरों ने कहा कि यह स्कीम बड़ी अच्छी है, इसलिए इसको चलाया जाए । इसको मुश्किल से 5 हजार रुपये से शुरू किया था, लेकिन सभापति जी, आपको यह जान कर खुशी होगी कि मेरे जिले में और मेरे क्षेत्र के आसपास करीब चार लाख बच्चों ने पोलियो, डिपथीरिया, टैटानस और व्हूपिंग कफ के टीके लगवाए हैं । इसके लिए सरकार और गैर-सरकारी दोनों का सहयोग मिला और साधनों की कमी नहीं हुई । जहां हम जाते हैं वहां साधन मिल जाते हैं इसलिए कि लोगों को बच्चों से प्यार है । जिन संस्थाओं, जिन लोगों और जिन डाक्टरों से कहा गया, उन्होंने हमारी मदद की । इसलिए इसमें पैसा कम लगता है, इरादे की ज्यादा आवश्यकता है और डाक्टरों को सेवाओं की ज्यादा आवश्यकता है । तो मेरा एक निवेदन होगा कि किसी भी तरह से सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर हम इस बात को अगर सोच लें इस सदन का प्रत्येक सदस्य यह सोच ले कि हम किसी बच्चे को रोने नहीं देंगे किसी बच्चे को लगड़ा नहीं होने देंगे और किसी बच्चे को डिपथीरिया नहीं होने देंगे, तो यह बहुत बड़ा उपकार बच्चों के साथ होगा और इससे हमारा बड़ा भारी कल्याण होगा ।

सरकार की ओर से बहुत से स्टैप्स लिये जा रहे हैं । आप हर एक विभाग की एनुअल रिपोर्टस को पढ़ लीजिए । उन सब में यह लिखा हुआ है कि सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट हैल्थ डिपार्टमेंट और एजूकेशन डिपार्टमेंट में क्या क्या काम किये जा रहे हैं । मैं उस पुलन्दे को यहां नहीं रखना चाहता हूं । मैं तो यहां पर यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हम सब इस बात की शपथ लें, आज उस महान् आत्मा के निर्वाण दिवस पर, कि हम बच्चों के आंसू पोछेंगे । यह पक्का इरादा आज करने की आवश्यकता है और मैं समझता हु कि इस सदन में बैठे हुए सारे सदस्य और माननीय सदन के सब लोग यह सोच लें कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है—इसमें कोई पालिटिक्स नही है, बच्चों के विकास के लिए कोई खाई नहीं है, कोई दीवार नही है—तो एक बहुत बड़ा इतिहास हम इस देश में बना सकेंगे । जिस दिन हमारे बच्चे मजबूत हो जाएंगे, हमारा इतिहास बन जाएगा । हम इतिहास के पढ़ने में विश्वास नही करते हैं, हम इतिहास को बनाने में विश्वास करते हैं । नया इतिहास बच्चों को मजबूत बनाने से ही बन सकता है और बिना बच्चों को मजबूत बनाए, नये भारत का इतिहास नहीं बन सकता है ।

सभापति जी, यह समिति जो बनी है, इस पर जो पोलिसी रिजोल्यूशन है, वह उस सदन के माननीय सदस्य बाबू गंगाशरण सिंह

[श्री डी० पी० यादव]

जी के सभापतित्व में बनायी गयी थी। जब यह समिति बनायी गयी थी, उस समय यह चिन्तन था कि एक समिति सारे देश में घूम कर देखे कि बच्चों की स्थिति क्या है। 1965 में यह समिति बनी थी, 1967 मे उसकी रिपोर्ट आयी, 1968 में उन्होने अपने विचार दिये और हमने उस पर कुछ काम करना शुरू किया लेकिन लाये इसको हम 1975 में। इस के लिए मैं क्षमाप्रार्थी जरूर हू। लेकिन इन्टेरिम रिपोर्ट पर हमने बहुत सारे काम शुरू किये जिससे बच्चों के रोग भगाने की अवस्था मे हम आये और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी बहुत से ऐसे काम किये गये जिससे बच्चो के रोग उन्मूलन का अभियान चला।

उस समिति की रिपोर्ट मे यह था कि चिल्ड्रन्स बोर्ड बनाया जाये। मैं समझता हू कि आज से करीब 6–7 महीने पहले, नवम्बर मास मे, शायद विज्ञान भवन मे एक सभा हुई थी। यह नेशनल चिल्ड्रन्स बोर्ड की प्रथम बैठक थी। प्रधान मन्त्री जी खुद उसमें आई थी। यह इसकी महत्ता का सबूत है। उन्होंने उसे सम्बोधित करते हुए कहा कि आपने बोर्ड बनाया लेकिन बोर्ड की वर्किंग को आप एक्सीलरेट कीजिए, इसकी एक्टीविटीज को हमेशा बरकरार रखिये। हम इतना भर कह सकते हैं कि बच्चों के विकास की एक्टीविटीज को त्वरित गति से चलाने के लिए हम कृत सकल्प है।

सभापति जी, जब बच्चों की बात आती है तो हम बापू जी को नही भूल सकते। उनकी एक तस्वीर है जिसमें कि वह एक बच्चे को गोद में लिये हुए हैं। वह तस्वीर सारे देश में फैली हुई है। उस तस्वीर से बहुत से लोगों को एक अफेक्शन है। उससे पता चलता है कि बच्चो से उन्हें कितना प्रेम था। किस प्रकार से वे बच्चो को उठाते थे, कही जाते थे, तो उन्हें साफ करते थे, उनको अच्छे ढग से रखने के लिए वे लोगो को उत्साहित करते थे। बापू जी ने बच्चो के बारे मे जो कहा उसका एक उद्धरण मे देना चाहूगा। उन्होने शिक्षा और बच्चो के सम्बन्ध में कहा है कि बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वह कैसी शिक्षा चाहते थे, उसी आधार पर हम नयी शिक्षा प्रणाली को और नयी शिक्षा पद्धति को ढालने की कोशिश मे हैं। महात्मा जी ने कहा था—

> "Real education has to draw out the best from the boys and girls to be educated This can never be done by packing ill assorted and unwanted information into heads of the pupils It becomes a dead weight crushing all originality in them and turning them into mere antomata"

हम मिअर आटोमेटा के पक्ष मे नही हैं। बच्चों के सम्बन्ध मे नये नये सिद्धान्त, नये नये एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं। उन्हें आदमी बनाने की हमे ज्यादा चिन्ता है।

मैंने कुछ अधिक समय ले लिया है। बहुत सारे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अन्त मे केवल यह दोहराना चाहूगा कि यह पॉलिसी रेजोल्यूशन है क्या। इसको मैं पोल स्टार की तरह से मानता हू। यह देख कर हमें दिशा निर्देश होगा। यह दिशा निर्देश

हमारे मंत्रालय के लिए, अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए होगा जो बच्चों के समग्र विकास में विश्वास करते हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी बच्चों के बारे में जो कहा है वह भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने साफ-साफ कहा है—

"I want the children of India to grow up interested in everything around them. I want them to use their minds and their hands. I want them to be proud of India and regard all Indians as equal."

यह शिक्षा हमें शिक्षकों को देनी है, विद्यार्थियों को देनी है, बच्चों को देनी है। अन्त मे इतना ही कहूंगा कि बच्चों का मन साफ होता है, उनका मन अपने आप साफ होता है, उनके तन को कैसे साफ किया जाय, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर, आप पर और सब पर है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सदन इस पर विचार करे।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House do consider the Government Resolution No. 1-14/74 CDD dated the 22nd August, 1074 on National Policy for children, laid on the Table of the House on the 26th August, 1974."

आज आखिरी दिन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आखिरी दिन इस प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए समय दिया हुआ है।

सभापति महोदय : इसके लिए पांच घंटे का समय अलाटेड है। करीबन बीस मिन्ट मंत्री महोदय ने ले लिये हैं तो अपने पास चार घंटे चालीस मिनट बचते हैं। सदन को छः बजे उठना है। (व्यवधान)

शाम को छः बजे हम को उठना है। अगर सदन चाहता है कि छः बजे के बाद भी बैठा जाये और इसको खत्म किया जाये. . .

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta-South): Sir, I have a suggestion. The discussion can continue in the next session also.

सभापति महोदय : छः बजे तक समाप्त इस डिसकशन को नहीं किया तो अगले सैशन मे यह जायेगा ही। आज जो मेम्बर बोल सकते हैं बोल ले। आराम से अगले सेशन मे इस पर और चार घंटे आप बहस कर सकते हैं। आज खत्म क्यों करते हैं। मेरे पास चौदह नाम हैं। और भी आ सकते हैं। आप चाहे तो दस-दस मिनट ले लें।

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Chairman, Sir, the resolution on National Policy for Children has been brought forth by the hon. Minister who has stated at the very outset that "let us wipe all tears from the eyes of the children." This is a very welcome statement and nobody can have any dispute with that nor can there be two opinions on it However, it is a matter of regret that this resolution which came 27 years after independence has been brought before this House for discussion two years after it was adopted in 1974. He has stated that provision for the welfare of the children is there in articles 24, 39 and 45 of our Constitution. Where in it has been provided that no children below the age of 14 shall be employed on jobs involving hard labour and in the factories etc. and free and compulsory primary education shall be provided for all children within 10 years. But how much have we achieved in this direction? He has stated that the Geneva Convention of 1924 and again in 1959 in the U.N.O., resolutions were adopted regarding the 10 point policy to be followed internationally In respect of employment etc. of children.

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Krishna Chandra Halder]

A decision has been taken at the international level as to what should be done for the welfare of children. But inspite of that we find that the children in our country living in far flung villages are living in state of utter neglect. Sir, I would like to place before you briefly the gravity of this problem. In 1961 the number of children in our country in the age group of 1—14 years was 17 crores 10 lakhs 95 thousand. In 1969 the number of children in the age group 1—14 went up to 20 crores 99 lakhs and 45 thousand. In 1971 that number went up to 23 crores 2 lakhs 53 thousand 9 hundred eighty seven. It is estimated that by the end of the 5th Five Year Plan, the number of children in the age group 1—14 will go up to 24 crores 32 lakhs 90 thousand. Further, from the figures available it is seen that the mothers who are giving birth to the future citizens of our country constitute about 22 per cent of our population and the children from 0—14 years of age constitute 40% of our population. Therefore we should take all possible measures for the welfare of the mothers and children who together constitute about 62% of our total population. Our various family and child welfare services should take care of the expectant mothers and the children in the following 5 stages. Firstly, the expectant mothers should be provided with adequate health and medical facilities so that they are in a healthy state at the time of giving birth to the future citizens of our country. Adequate pre-natal and post-natal medical care must be provided for the mothers. Secondly, special care must be taken of the children from birth to one year. The third stage is from one to three years. The fourth stage is from three to six years. It is school stage. The fifth stage may be called the primary school stage and this will be from 6 to 14 years. Special care must be taken in the above mentioned five stages for proper development and welfare of the children. This shows how vast is the problem before us and how much have we been able to do in face of this grave problem.

Sir, let us now compare the birth and child mortality rate in country with those of some other countries:

Country	Year	Rates per 1000 birth	Rates per 1000 death
India	1965-70	42·8	16·7
Great Britain	1973	13·9	12·1
Italy	1973	16·0	9·9
Pakistan	1968	36·0	12·0
USSR	1973	17·7	8·7

From the above figures it is clear that the birth rate in our country is very high but at the same time the child mortality rate is also very high. The only reason for this state of affairs is acute poverty in our country where about 70% of the population live below the poverty line and 75% of the people live in the villages. Among this huge percentage who live in villages, the largest number constitute the share croppers, poor agricultural workers, landless labourers etc. and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who work in the fields and in the factories. These people live in acute state of poverty

and the rate of child-mortality is also the highest among them. Therefore, unless we divert our attention from the cities to the rural areas, it will not be possible for us to take any meaningful child welfare activities. We will have to pay much more attention to the village people, where most of our population live. In our country where about 4 crores and 50 lakhs of people are suffering from blindness, the number of children suffering from blindness are about 90 lakhs which fall in the age group of 1—5 years number about 2 lakhs and 50 thousand. These figures were given in the Lok Sabha in reply to an Unstarred Question. Therein it was also said that there are about 14 thousand children who withering for want of proper nutrition and lack of vitamin etc. The Government and the society has a responsibility not only towards the present citizens but also towards the future generations to be healthy, physically as well as mentally, then we will have to take proper steps right from now. With that object in view I am trying to show how grave and deep rooted the problem is and how little the Government and the society has been able to do for the welfare of the coming generations. Mr Chairman Sir, you are aware that in the national policy for children it has been contemplated to set up National Children's Board. This Board was formed two years earlier but all the work has been done by this Board during the last two years is not known. The hon. Minister has not also said anything about the work done by this Board. Sir, the welfare activities for the children is not confined to the Ministry of Education and Social Welfare alone. The Ministry of Health has also to play an important role. It has of course been said that the National Children's Board is coordinating an Advisory Body. In our language there is a saying that 'everybody's business is nobody's business.'. Since the responsibility for the children's welfare is divided between the Ministry of Education and Social Welfare and the Ministry of Health, no effective measures has been possible because of the lack of cooperation between these Ministries. As a result the tender children of our country are in a state of utter neglect. There must be proper coordination between the various Ministries so that speedy and effective measures can be taken for the welfare of the children. I want to suggest one thing about the formation of this Board. It has been stated that this Board will consist of 29 members. The Prime Minister is to be the President of this Board and the Minister of Education and Social Welfare is to be its Working Chairman. The Minister of Health and Family Planning will be a member and 10 more members will be appointed from various Social Welfare Organisations etc. having knowledge and experience of various styles on welfare activities and some other categories of members are also to be appointed on this Board. Here, Sir, I will like to say that these members who will be appointed from the various social service organisations mostly from the urban areas, their activities and experience are confined to the urban areas alone. They know next to nothing about the conditions prevailing in our villages, they do not know our village people at all. There may be some lady members coming from these urban organisations who do not know the conditions of the share croppers and the agricultural labourers working in the fields and farms they hardly know our country itself. Therefore I will urge upon the Government to raise the number of members on the Board from 29 to 37.

17 hrs.

I hope the Government will accept my suggestion. Out of these 8 additional members 4 may be appointed from various Central Trade Unions, those will have adequate knowledge and experience of the living conditions of the poor workers in factories and farms. Many children are employed in the jute mills, tea gardens, and in the rubber plantations. There are many working mothers also in the trade unions. If four members are

[Shri Krishna Chandra Halder]

taken from these trade unions, they will have intimate knowledge and experience about the conditions of these poor children and they will be helpful in planning welfare measures for them. Four other members may be appointed from the Central Kisan Sabha. Thus the total membership may be raised to 37 as suggested above. In our Constitution it has been provided that no children upto the age of 14 years shall be employed on any job involving hard labour. But our Government representatives had stated there that it is not possible for India to accept that decision. In this context I will quote a news item appearing in the 'Satyajug' paper dated 24th May, 1976 in which our Government's spokesman says, "the decision taken in 1973 by the ILO cannot be accepted by India. That year the ILO had decided to abolish the appointment of children below 14 years of age on job involving hard labour. But India cannot accept that decision just now because the children in India constitute 5.9% of the total labour force of this country." This attitude of the Government is not proper. They should strive to create conditions which will discourage the employment of children on hard labour jobs. They should provide employment to the adult members of the family from which child labour is engaged. Poverty after all is the root cause of this evil. If the adults get suitable employment opportunities, the children will not have to seek employment on jobs involving hard labour. If real land reforms are effected, if land is given to the tiller, if the poor share croppers, the landless agricultural labour, the scheduled castes people are given ownership of land and if the "right to work" enshrined in our Constitution is accepted and implemented by the Government and proper and adequate employment opportunities are provided in the factories and firms then I believe this evil practice of employing children on hard labour can be abolished. Sir, in this context It will say that unless the Board which has been formed is made financially viable, it will remain ineffective like the National Integration Council. This will remain in name only and will not be able to achieve much for the real welfare of the children. Sir, in 1968 it was estimated that about 0.5% of the child population of our country numbering between 1.05 million and 1.15 million were orphaned or abandoned children. The number of children's homes available for looking after and bringing up such children is very inadequate. Government should set up more children homes to look after their physical and mental health and other requirements and to provide educational facilities to these unfortunate children so that they may grow up as responsible citizens of the country. A study made by the Central Social Welfare Board regarding conditions in our orphanages revealed that on an average of Rs. 22 is spent per child per month on food and Rs. 9 is spent on medicine. I fail to see how these children can be brought up in a healthy manner with this meagre amount. Then Sir, according to a report published in the *Hindustan Times* dated 5-4-76, a meagre sum of Rs. 1.30 crores has been earmarked during 1976-77 for the Integrated Child Development Scheme which is to finance 33 integrated child development projects in various States. How much can be achieved with this pittance in this respect is anybody's guess. The Government should be realistic in the financial allocations if they want to achieve anything concrete.

Another report published in the *Hindustan Times* dated 29-3-76 says that only 37 per cent of the Children get their share of food distributed for the children, and 82 per cent of the milk given for the children is used for making tea etc. and the children hardly get any benefit due to *malafide* distribution. This should be thoroughly investigated. Moreover, this facade of distribution of food and milk for the children is confined to the big metropolitan cities like Delhi, Calcutta, Bombay, Madras etc. Nobody is bothered about the rural areas where mostly the poorer classes like the share croppers,

agricultural labourers, scheduled castes and tribes etc. live. The most deserving children are denied any benefit in this respect. The Government speaks about providing free and compulsory education but are they aware that thousands of children have to drop out at the primary stage due to acute poverty. This is a very serious matter. Sir, no "maternity homes" and other medical care is available for the expectant mothers belonging to these poor and neglected classes in the villages. Maternity homes should be set up in the rural areas for providing pre-natal and post-natal care. Unless attention is paid to these things any number of 'Boards' cannot serve any real purpose.

I will conclude by saying that the present social system in our country needs to be radically changed. So long as the exploiting social system is in existence, any thought of welfare for the poor masses is bound to remain a wishful thinking only. In the present system no equal development is possible. Therefore we must strive to bring about radical change in the present social structure than only we can think of real welfare for the poor masses. I hope Shri Priya Das Munshi, hon. Member will agree with me in this respect.

श्री जगन्नाथ मिश्र (मधुबनी) : सभापति जी, चर्चा का विषय बड़ा ही गम्भीर है और उसी गम्भीरता से हमे उसको लेना है। मंत्री महोदय ने बाल विकास के सम्बन्ध मे जो व्यापक व्याख्या दी है, बालकों के विकास के लिए जितनी व्यग्रता, उत्सुकता प्रकट की है उससे देशवासियों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इस विषय पर कोई प्रकाश डालने के पहले मुझे एक अंग्रेजी की कहावत स्मरण हो आई है :

"The king is dead; long live the King."

इसके साथ मैं अपनी ओर से एक नया नारा जोड़ना चाहता हूं—बच्चे पैदा न करो, बच्चे की देखभाल ठीक से करो :

"Don't produce a child: look after the child carefully".

आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चे कम पैदा करें और जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनकी यथोचित देखभाल हो। मंत्री महोदय ने सुझाव की माग की है अत. इस विषय पर व्यापक प्रकाश डालने के बजाये मैं सुझाव ही देना शुरू करूंगा।

मंत्री महोदय ने बच्चे को एज ए होल ट्रीट किया है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि मे, देश की जो आर्थिक स्थिति है और जो सामाजिक स्थिति है उसको भी अपने विचार मे रखना होगा। कई बच्चे हैं जो सुखी और सम्पन्न परिवार में पैदा हुए हैं उनके लिए हमको और आपको क्या चिन्ता करनी है? कुछ बच्चे हैं जो गरीब तबके के लोगों के बीच पैदा हुए हैं जिनको वे उचित पोषण नही दे सकते हैं। कुछ अनुचित बच्चे भी पैदा होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नही होता है। लेकिन बच्चे पैदा हो लेते हैं तो सरकार की जवाबदेही इस तरह से ग्रेडेशन करने की होगी, जिनमे ऐसे बच्चों की देखभाल हो सके। बच्चे जो समाज में हैं, कैसे बच्चे हैं और किस तरह के बच्चे हैं और किन को किस चीज की जरूरत है, इन सब चीजों के लिए ग्रेडेशन तैयार करना होगा। तो सब से पहले मैं यह कहूंगा कि उन बच्चों

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

के लिए, जिनकी पैदायश हो गई है लेकिन पैदा करने वाले का कहीं पता नहीं है वे अनाथ हो गये हैं, गृहविहीन हैं और इल्लीगल हैं, ऐसे बच्चों के लिए सोचना सरकार का काम होता है। उनके लिए ऐसे गृहों का निर्माण हो जहां पर उनकी देखभाल यथोचित हो सके।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण): कलकत्ता में मदर टेरेसा द्वारा ऐसा होम चलाया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : जहां पर इस तरह का काम हो रहा है उसके लिए हम और आप दोनों धन्यवाद देते हैं लेकिन देश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर इस तरह का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां पर इस तरह के होम्स खोलने चाहिए।

सभापति महोदय : आप किसी बच्चे को इल्लीगल चाइल्ड नहीं कह सकते।

श्री जगन्नाथ मिश्र : इसीलिए मैंने पहले कहा था प्रोब्ल्म भी चाइल्ड।

सभापति महोदय : इल्लीगल चाइल्ड नाम की कोई चीज नहीं है। (व्यवधान) . . .

श्री जगन्नाथ मिश्र : श्रीमन्, मैं एक बात की ओर दुःख के साथ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और वह यह है कि बच्चों के लिए चाहे सरकार हो या चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हों, वे जो भी मदद करने को तैयार होती हैं, मुझे संदेह है कि बच्चों को ठीक से वह सहायता पहुंच पाती है या नहीं? नहीं पहुंच पाती है। मैं यहां दिल्ली में हूं और यह देखता हूं कि दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए उनकी मां एक बर्तन स्कूल में लेकर जाती हैं और उसमें दूध होता है, कैसा दूध होता है और कितना दूध होता है, यह तो मैं नहीं जानता और इसके बारे में मंत्री महोदय ही बता सकेंगे। देहातों और गांव की बात अगर कही जाए, तो यह चर्चा केवल पार्लियामेंट में हो सकती है, पार्लियामेंट के बाहर कुछ नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने आपकी किताब को पढ़ा, रिपोर्ट को पढ़ा और बहुत सी पत्रिकाएं देखीं जिस में मैंने पाया कि सरकार बच्चों के प्रति बहुत जागरूक है और बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन मैं अचम्भित हो गया और अचम्भित इसलिए हो गया कि यह सब सहायता जाती कहां है और किस के लिए यह हो रहा है। तो पहला सुझाव तो मेरा यह है कि जिन बच्चों के लिए जो भी आप कर पाते हैं वह उन तक पहुंचे।

मेरा अगला सुझाव यह है कि बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था सरकार की तरफ से या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा होती है, उससे उन बच्चों को कभी वंचित न किया जाये। वह आहार बच्चों को मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की एक ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी चाइल्ड एडाप्शन बिल के बारे में विचार कर रही है। वह विचार अभी सम्पन्न नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है और अभी उस पर विचार चल रहा है। यह एक अच्छा संकेत

है, एक अच्छा कानून और जैसे बच्चों की जैसे चर्चा की है उसका इस बिल के पास हो जाने से फायदा हो सकेगा। अभी इस एडाप्शन बिल पर विचार ही चल रहा है और सारे देश में वे लोग घूम रहे हैं और वह इनेक्टमेंट नहीं बन पा रहा है। तो मैं समिति से आग्रह करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी इस सदन में वह बिल पेश करे ताकि इनेक्टमेंट बनने के बाद बच्चों की देखभाल ठीक से हो सके। मैं सदन से भी और कमेटी से भी निवेदन करूंगा कि इस काम को जल्दी किया जाये।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अरक्षित हैं, उन की कोई देखभाव नहीं होती है, वे अनाथ पड़े हुए हैं, उन को अगर कोई शरण देने वाला हो सकता है तो आप ही हो सकते हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हो सकती हैं। वे बच्चे शरण के अभाव में मर जाएं या मरते हुए जिन्दा रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह मेरा विचार है।

17.20 hrs.

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

बोर्ड का संगठन करने वाली जो बात आप ने कही है, वह बहुत सुन्दर बात है। उस का जो काम होगा, उस पर मैं बाद में विचार करूंगा। बच्चे किस वातावरण में पल रहे हैं इसका भी ख्याल आपका करना होगा। अगर उनके मां बाप दूषित वातावरण मे रह रहे हैं तो बच्चे से कैसे आप आशा कर सकते हैं कि वह उस वातावरण से निकले। इस वास्ते इनविरनमेट का भी आपको देखना होगा। उस वातावरण, में से आपको उसको निकालना होगा ताकि उसका मानसिक विकास ठीक से हो सके। कहा जाता है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बाडी। अगर वह शरीर से तनदुरुस्त नहीं रहेगा तो उसके मन का विकास कैसे हो सकेगा। बच्चे राष्ट्र की निधि कहलाते हैं। सम्पत्ति कहलाते हैं, धन कहलाते हैं। किन्तु बच्चे राष्ट्र का धन हैं, इतना कह देने से वे धन नहीं बन जाएंगे। धन बन सकें, इस लायक आपको उनको बनाना होगा। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आज तक यह नहीं हुआ है। आज आप इस पर सोच रहे हैं, यह आपकी बहादुरी है, वह आपका और सरकार का बड़प्पन है, सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन कर रही है। इस में कोई दो रायें नहीं हैं कि काम कठिन है और मुश्किल है। इस वास्ते इसको पूरा करने के लिए वैसी मुस्तैदी की जरूरत है।

बच्चे के स्वास्थ्य के पहले आपको उसकी मां के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिये। मां बीमार है तो बच्चा भी बीमार पैदा होगा। अगर मां तन्दुरुस्त है, उसका बच्चा भी आम तौर से तन्दुरुस्त होगा। अगर मा को पोषक आहार नहीं मिलता है, अगर वह दूषित वातावरण मे रहती है तो बच्चा कैसा पैदा होगा इसकी सहज ही आप कल्पना कर सकते है। इस वास्ते बच्चे के साथ साथ उसकी मां को भी देखभाव आपको करनी होगी। उनकी जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश भी आपको करनी होगी। मैं समझता हूं कि दो तरह के काम आपको करने होंगे। देहातों के लिए एक तरह के और शहरों के लिए दूसरी तरह के काम आपको करने होंगे। दोनों जगह आप एक तरह नही कर सकते है। देहातों का वातावरण एक तरह का है और शहरों का दूसरी तरह का होता है। मेरा सुझाव है कि देहातों के लिए आप परिवार कल्याण योजना लागू करें, फैमिली वैलफेयर प्लानिंग सेंटर चलाएं। अस्पतालों को ग्रामीण इलाकों मे व्यवस्था होनी चाहिये। अगर हर जगह अस्पतालों की व्यवस्था सम्भव नही है तो वहां आप स्कूल हैल्थ टीम्ज इनक्लूडिंग डैंटल क्लिनिक्स स्थापित करें, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करें। वे तो

[श्री जगन्नाथ मिश्र]

आप जहां तहां स्थापित कर ही सकते हैं। वहां उनके तुरन्त उपचार की व्यवस्था होनी चाहिये, दवा दारू उनको मिल जाना चाहिये।

शहरों में मेटरनीटी बेड्स की जिस को मातृ सेवा सदन कहते हैं आप स्थापना कर सकते हैं। स्कूल हैल्थ टीम्ज आप स्थापित करे। साथ ही साथ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स की स्थापना करे। इस तरह से बच्चो के स्वास्थ्यवर्धन का काम आप कर सकते है।

बच्चो को पौष्टिक आहार मिले इसके लिए भी आपको कार्यक्रम निर्धारित करना होगा।

यह सब कुछ हो जाए तो आपको बच्चो की पढाई की व्यवस्था करनी होगी। बच्चो की सेवा और शुश्रुषा ठीक से हो उनकी देखभाल ठीक से हो, उनके विकास मे किसी तरह की बाधा न आए इसकी भी जवाबदेही हम सब पर है इसके लिये आवश्यक है कि बाल साहित्य की रचना हो और बाल वाचनालय जगह जगह खुलें। हर गाव और हर मुहल्ले मे छोटी-मोटी लाइब्रेरीज की व्यवस्था आप करे और जहा बच्चे जाए और किताबे आदि पढ सकें। इस कार्य मे स्वैच्छिक सस्थाओ का सहयोग भी आपको लेना चाहिये और उनका भी आह्वान आपका करना चाहिये। उनको हर तरह से मदद देनी चाहिये, उनको प्रोत्साहित करना चाहिये। यह बहुत बडा काम है। यह केवल सरकार के बलबूते की बात नही है। इसलिए वालेंटरी आर्गेनाइजेशज का सहयोग लेना आवश्यक है और उसका लिया जाना चाहिये।

आपको विकलांगो के लिए भी कार्यक्रम बनाने होगें।

शहरों मे तो बच्चे फिल्म देख लेते हैं और अपना मनोरजन कर लेते हैं। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो इसके लिये आप को चाहिये कि आप गांवों में भी फिल्में दिखाने की व्यवस्था करें।

राष्ट्रीय विकास और उत्थान में बच्चो के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने 22 अगस्त 1974 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय विकास नीति का निर्धारण किया था। इसमे सरकार ने पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम रखा। इसमे यह व्यवस्था थी कि बच्चों के स्वास्थय, पौष्टिक आहार, अनाथ एव विकलाग बच्चो एव दुखी माताओ की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाये और उसके लिये योजना बनाई जाए। इस हेतु प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता मे नेशनल चिल्डरज बोर्ड की स्थापना हुई जिसकी प्रथम बैठक 3 दिसम्बर, 1974 को हुई। इसी के आधार पर और इस राष्ट्रीय नीति के अनुपालन के लिए प्रान्तो को गाइड लाइज भेजे गए। इन गाइड लाइज के आधार पर बहुत से प्रान्तो ने काम करना शुरू किया। केन्द्र शासित प्रदेशो मे भी इनके अनुसार काम चला। 14 नवम्बर, 1975 को बाल दिवस के नाम पर एक स्टाम्प का प्रकाशन हुआ। इसके बाद चतुर्थ योजना तक 2 29 लाख बच्चो को लाभ पहुचाने की दृष्टि से सेंट्रल सोशल वैलफेयर बोर्ड, इडियन काउसिल फार चाइल्ड वैलफेयर भारतीय आदिम जाति सेवक सघ और हरिजन सेवक सघ के सहयोग से बच्चो को सहायता पहुचाने के लिए 37 लाख रुपया स्टेट्स को देकर बच्चो के लालन-पालन मे उसका व्यय करवाया। पाचवे प्लान मे इसे स्टेट सबजैक्ट करार दे दिया गया है। 1975-76 मे 89,000 टन अन्न उनको दिया गया है जिसका मूल्य बीस करोड रुपये होता है। इसका वगठन करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन भी एस्टैबलिश किया है। इण्डिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से 15.85 लाख मूल्य का अन्न प्राप्त किया गया है। इंटेग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं जिनका उद्देश्य है कि वे बच्चो के स्वास्थ्य का

विकास करें। उनकी साइकालोजिकल और फिजीकल स्थिति का डेवलपमेंट हो और उसके बाद मां की कैपेसिटी भी तरक्की करे, इस तरह की व्यवस्था इन्होंने की है।

उसके बाद हैल्थ- सब- सेंटर भी खोल दिया है। 5 हजार की आबादी पर एक वैदिक या डाक्टर का इन्होंने इन्तजाम किया है। यह तो दाल में नमक के बराबर भी नहीं हुआ। इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इनकी संख्या बढ़ा दें।

1975–76 में 132.37 लाख रुपये की सहायता मिली है। उससे 245 वालेन्टियर आर्गेनाइजेसन्स को सहायता दी जायेगी जिससे 15,905 बच्चों की देखभाल हो सकेगी। बाल सेविका संस्था ने इन्तजाम किया है। इसमें इन्होंने 11 महीने की ट्रेनिंग रखी है। सेंट्रल को-आर्डिनेशन कमेटी, मैंने पहले कहा था कि यह अकेले शिक्षा मन्त्रालय का काम नहीं है। मैंने कहा कि बच्चे पैदा न करो, बच्चों की देखभाल ठीक से करो, इसका मतलब स्वास्थ्य मन्त्रालय से होता है। इसलिये विभिन्न मन्त्रालयों का आपस मे को-आर्डिनेशन होना चाहिये, तभी यह स्कीम सफल हो सकती है। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये, यह बहुत जरूरी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक को-आपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट के अन्तर्गत सामाजिक विकास के लिये स्वैच्छिक काम को बढ़ाकर ये बच्चों का विकास करेंगे, इसकी भी व्यवस्था की है। इसके लिये मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं आशा करता हू कि मन्त्री महोदय अपना जवाब देते हुए उस पर अवश्य प्रकाश डालेंगे।

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): I listened to the speech of the Hon. Deputy Minister for Education. The speech was emotion-charged. He recalled the association of Panditji with children. It is on this day that Panditji left us. It is a coincidence, most probably, that this Resolution has been brought before the House for discussion and suggestion on this day. As the Minister has told us, the national policy was framed in 1974. It has been taken two years now. He has himself said that the Committee under the Chairmanship of Shri Ganga Saran Singh, submitted a report in 1968. Government took some time to process it. Most probably it started acting upon some of the recommendations made in the report and the Report of the Ministry contains a catalogue of the various work done by the Ministry in this regard.

I must assure the Minister that on this particular question, there can be no question of any political difference. We are all agreed on this question that the children should get the utmost attention and care. They are the nation's biggest assets and whatever we do for their development, growth and welfare should be construed as an investment or the means of developing human resources which would ultimately strengthen the nation. And from that point of view, the nation should be assured of all co-operation from all parties.

I must also compliment him for the work that he has done in his own district and set an example to the people as to how voluntary work could be done without the help of any organised State assistance. But I would like him to carry this message of child welfare or voluntary work to other districts in his own State So far as this subject is concerned, I must tell you that the welfare work cannot take place without involving the people, voluntary agencies working for this purpose, and the support of State in this task.

Here, I would like to point out that the problem of child welfare is a gigantic problem. It is a clossal problem and if you look at the figures worked out by the Ganga Sharan Singh Committee you will be convinced that the problem does not mean

[Shri Satyendra Narayan]

only the welfare of the child but it also includes the welfare of the pregnant women and nursing mothers. According to what Committee, the child population, pregnant women and nursing mothers constitute 62 per cent of the total population. This would mean that a population of about 300 million was to be taken care of through welfare services in terms of health, nutrition, education and other welfare activities. And if you take the present total population of 600 million, this percentage would work out to about 37 crores people in the category. That means 37 crores. So, we have to take into consideration the needs of the welfare services of these people in terms of health nutrition, education and other welfare activities.

17.35 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

The problem has been made more complicated by the present trend of urbanisation. People are now going to the cities because industrial development has made a change in our whole environment. Cities have grown up giving rise to slum areas. People in search of employment go to cities, stay in slum areas and their families are exposed to such conditions which do not conduce to a healthy living. While looking at the welfare problem of the child, we have to see not only to nutrition and education but also to the environment of the child. We should look to the socio-economic condition of the family; the general conditions in which the child lives, the society in which he lives, the company he keeps, the attitudes and habits of his parents and those around him—all these factors have to be taken into consideration in determining the line of activities to deal with particular areas where those children live.

I know the government is aware of these problems and have started work on many fronts. They have been trying to provide nutritious food, medicines, hostel facilities supplementary support etc. to families but whatever the government has done so far cannot be considered very significant against the background of the colossal task before us. I do not blame them, but I do feel that the task is so gigantic that it requires much more effort than what is being put in. Government have made a provision of Rs. 200 crores during the fifth plan for the social welfare sector. I will take the case of destitute children, children who have been abandoned, who have no home and are on the streets. You might have seen children begging on the streets near sweet shops, pan shops etc. These are the children who ultimately become delinquents. No survey has been carried out of them. The Planning Commission Study Group which went into it provisionally gave an estimate of the figure of destitute children who according to the Study Group from 0.5 per cent to the total children population, according to which their number comes to 1.05 million. Most of them are in orphanages. We do not know the number of orphanages run in the country. Government has no figures as to how many children are in these orphanages and what are their conditions. A survey ought to be carried out to find out the actual number of destitute children. Government has not given us any figure about the number of orphanages being run. We understand that the Christian Missions are running about 600 orphanages. Some private institutions also are running orphanages. Government should have brought out what are the conditions obtaining there. According to a limited study of 100 orphanages, it appears that the conditions in these orphanages are not satisfactory. They are not able to provide services of a high standard. According to the study report, it appears in these orphanages the expenditure on food is Rs. 22 per child and on medicines Rs. 9. it has been found that in the orphanages, the survival rate of children is very low i. e. one out of three. Mrs.

Tara Ali Beg has stated that the mortality rate in the orphanages and in foundling homes is as high as 60 per cent. After a study of only a few months, a decline in the I.Q. of these children is noticed. Now, the question is, how are you going to improve the situation?

There is another way. These children could be adopted by people. Unfortunately, there is no law here which will give a scope to people of different communities to adopt children could be adopted by people. according to which the Hindus alone can adopt children and that too from Hindu families. Shrimati Jayashree Raiji had brought forward a Bill for adoption but that was not allowed to be passed. After that, three more attempts were made to bring the Bill in the House, but nothing had happened. At last, the Government brought forward a Bill which was referred to the Joint Committee and it is still pending there. The problem of the destitute children is very serious. Government should take steps to get the Adoption Bill passed. It should provide scope for foreigners to adopt children. At one time, several States raised several objections and the practice of adopting children by foreigners was completely stopped. A report was published in the Press by Mr. Chhabra who made a study of the adopted children in the Scandinavian countries. There are some organisations who look after these adopted children who are adopted by the foreigners. It was found that they had not been put to any kind of ill treatment. Now this type of law should be there.

I would like to make a submission that there is a Guardian Act of 1890 according to which you can take custody of a child and keep him for 18 years. But it does not provide any legal right to these children as in case of adopted children. It has also happened that parents have turned up after several years to claim their offspring. There is uncertainty and insecurity with respect to the position of such children taken under "foster care". Government should make a law whereby the difficulties which these destitute children were facing, should be removed.

I may submit here that there are voluntary organisations which are looking after these children and implementing special Nutrition Programme. The National Institute of Public Cooperation and Child Development carried out a study of some centres recently. They have said that those organisations who are organising the special nutrition programme have not been very fair. Only 37 per cent are taking benefit out of it. The records at the Centres are not unreliable. Attendance marked after food distribution is only a formality at almost all the Centres. Food for 10 to 12 children is left over and is utilised by the organisers and their helpers Correct information is not disseminated Parents do not know the food entitlement of the children. I want to know whether a similar study is under contemplation of the Government with regard to oher centres not only in Delhi but elsewhere also so that we should know as to what is actually being done. We have got some Model Homes run by Mother Benigna or Mother Terassa,—her "Sisu Bhavans." I would request the Government to encourage voluntary and other organizations running such homes to emulate their example and to entrust the work to people who are genuinely actuated by compassion and love and who do not take it up as a matter of fashion. From destitution to delinquency, the road is very smooth and the line vary thin. When they get into delinquency, these destitute children ultimately turn out to be vagrants, start doing small mischief and then they commit theft and other offences. I think a proper study ought to be made about these cases. They are governed by the Children Act. Government have said in their report that they have also discovered certain lacuna-

[Shri Satyendra Narayan]

in regard to the working of the Children Act and that they are contemplating to amend the Act. My submission would be that they should also study the report of the Study Team appointed by the U.N Council of Social Science Research. They have made a study in Madras, Delhi and Bombay; and have reported that there is need for a careful screening system of juvenile cases at pre-and post-disposal levels. It has been seen that in some cases where the child is in a pre-delinquent stage, he is sent the juvenile court; and where the child is actually delinquent, he is sent to the Child Welfare Board for being looked after. There is some kind of a lacuna, *viz.* that once a child is sent to the children's court, the difficulty would be that he cannot be reverted back. There is no system of inter-changeability in it.

The study team appointed by this Council has said that a screening system should be worked out through classification centres comprising the representatives of police, the legal department, and the mental-health and social-work personnel. These classification centres should replace the present system of hurriedly branding the children as juvenile offenders and non-juvenile offenders, by the police. These lacunae in the Children Act should be removed. I hope the Government will take early steps to amend this Act.

I now come to the question of physically handicapped children. According to their own estimate, about 5 per cent to 10 per cent of the child population is handicapped. According to the Ganga Saran Singh Committee, the total number of handicapped children would come to 1.8 million. According to them, the children afflicted by blindness would be 0.5 million, by deafness 0.2 million, orthopaedically handicapped 0.5 million and that those mentally retarded would number 0.2 million. In other advanced countries, it is estimated that nine per cent, more or less, of the population is made up of handicapped children. On that basis, they came to the conclusion that there will be 18 million handicapped children in India.

Now, they feel that these physically handicapped children are not receiving adequate attention and that most of thesse children have suffered because of some kind of social neglect, income disparity, conditions in the society and mal-nutrition.

The other day, I have come across a report in the paper that 14,000 children are suffering from blindness only in the South. Now, the Government have started giving Vitamin. And D capsules to these children and they are also extending this scheme to the North. But every effort has to be made to develop a proper social attitude towards these children. It is not sufficient to educate them. It is very difficult to find employment for them after they are actually trained.

The Committee under the Chairmanship of Shri Ganga Saran went into this question in depth and reported that in order to deal with these physically handicapped children, to rehabilitate them, to restore them to a position so that they become useful to the society, it will cost Rs. 3,555 crores. This is a colossal sum. They have also said that it is not beyond the resources of the Government to do it. Therefore, they have suggested that it is better if we deal with only 20 per cent of the population in the next 20 years and not immediately. We should make a modest beginning in this regard and 20 per cent of this population should be treated, restored to the position so that they become useful to the society and rehabilitate them in the next 20 years.

I should have liked to hear from the hon. Minister when he was referring to the Ganga Saran Singh Committee's Report as to what they have thought about this suggestion. They have mentioned about these physically

handicapped children and that they are going to set up five national institutes. May I submit that they have not been able to deal with this subject on a massive scale? At the most, they can make slight change here and there. It requires a larger effort. I agree that financial constraints are there, the Government cannot do it alone and the responsibility also devolves upon the people, the voluntary organisations and the society. It is our job to co-operate with the Government in this great endeavour for the welfare of the children and for the proper growth and development of the children so that they become good citizens.

Therefore, I would say that in this year which is a national year for the children, Government should launch a programme by which you can create a national consiousness and awareness among the people which will assume the shape of a national movement backed by the Government so that people could come forward to take upon themselves the responsibility for looking after these children.

I know that the country is moving on the road to progress. We are going ahead. The Government is also aware of the problem of slum areas. They are also aware of the problem of the landless population which is one-third of the entire population. Naturally, they have to initiate programmes in which they could get people's cooperation with enthusiasm.

The hon. Minister cited the example of his district, how he initiated the programme whereby without governmental support, he has been able to fight the scourge of whooping cough, diptheria and tetanus. Similar efforts have to be made elsewhere and on the same popular front. Then alone we can fight this challenge, meet this challenge posed by the gigantic problem.

Once, again, I would submit to the hon. Minister that while replying to the debate in the next session, whenever it takes place he may consider these suggestions, how he is going to enlist the support of the people, how he is going to create national consciousness and how he is going to create national movement so that the child welfare work is considred as the responsibility of the entire population and the entire nation.

With these words, I thank the hon. Minister for giving us an opportunity to discuss the National Policy for children.

MR. SPEAKER: The debate will continue later on.

17.57 hrs.

STATEMENT RE:

PAYMENT OF BONUS TO L.I.C. EMPLOYEES

MR. SPEAKER: The statement to be made by the Finance Minister, Mr. C. Subramaniam.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, before the Finance Minister makes a statement, I would like to say that the point raised by me and by Mr. Somnath Chatterjee was that on 21st of this month, Calcutta High Court gave a judgement declaring that the reduction of bonus was illegal and *mala fide*. Whether it is the Government or the LIC, we do not know, they asked for a stay order before the Division Bench of the Calcutta High Court and the Division Bench disallowed it.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): The hon. Member may be more up-to-date with regard to the information. I am giving whatever information I have.

Mr. Speaker, Sir, Hon'ble Members are aware of the policy decisions taken by Government in regard to payment of bonus. Employees of the LIC/GIC and Banks are not covered by the Payment of Bonus Act, 1965 and